प्रेस विज्ञप्ति

गोरखपुर 12 जुलाई 18। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए आवास, औद्योगिकरण आदि में कृषि भूमि बड़े पैमाने पर घटती जा रही है जिससे कृषि भूमि का आकार सिकुड़ रहा है, इसे जनपद में उपलब्ध समस्याग्रस्त भूमि को खेती योग्य बनाकर क्षतिपूर्ति करना नितान्त आवश्यक है। जनपद को कृषि की अच्छी उत्पादकता के लिए एंव समस्याग्रस्त क्षेत्रों के भूमि सुधार के निराकरण हेतु काम्प्रिहेन्सिव प्लान बनाकर अमल की आवश्यकता है।

जिलाधिकारी के विजयेन्द्र पाण्डियन ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला भूमि एंव संरक्षण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उक्त उद्‌गार व्यक्त किये। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्राकृतिक जलाशय तथा विगत वर्षों में बनाये गये जलाशय गाद के कारण अपनी जल संचय क्षमता खो रहे हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव के कारण खेती योग्य जमीन आवासीय भूमि में परिवर्तित हो रही है तथा औद्योगिकरण एंव नई नई सड़कों के निर्माण से सभी जलभराव की समस्या उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार जहां एक तरफ भूमि संरक्षण के उपाय अपनाकर बीहड़, बंजर, ऊसर जलमग्न भूमि को सुधार कर खेती योग्य बनाया जा रहा है।

जिलाधिकारी ने कहा कि आवश्यकता इस बात की है कि भूमि संरक्षण के उपाय निरन्तर अपनाये जायें जिससे बाढ़, सूखा आदि के कारण मिलने वाली चुनौतियों से निपटने में सुविधा हो। इन उपायों से सूखा एंव बाढ़ के कारण पैदा होने वाले विकार से घटने वाले कृषि क्षेत्र की भरपाई होती रहेगी और कृषि विकास को स्थायित्व मिलेगा।

जिलाधिकारी ने एजेण्डावार विस्तृत समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि भूमि संरक्षण विभाग द्वारा जो कार्य कराये जायें उसकी जानकारी जन प्रतिनिधियों को भी अवश्य दी जाये तथा कार्यों का सत्यापन अवश्य हो। उन्होंने कहा कि कार्य प्रारम्भ से पूर्व, मध्य तथा पूर्ण होने पर उसकी फोटोग्राफी जरूर करायी जाये।

बैठक में विधायक खजनी सन्त प्रसाद, ब्लाक प्रमुख खोराबार शैलेष कुमार यादव, मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे। बैठक का संचालन उप निदेशक भूमि संरक्षण ने किया।